चीनी का बफर स्टॉक बनेगा, तय होगा मिनिमम एक्स-मिल प्राइस!

[एजेंसी | नई दिल्ली]

नकदी की तंगी झेल रहे चीनी उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने और चीनी का न्यूनतम एक्स-मिल प्राइस तय करने के लिये कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। चीनी मिलों के नकदी संकट के चलते किसानों का गन्ने का बकाया 22,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन होने और दाम गिरने से यह संकट खड़ा हुआ है।

खाद्य मंत्रालय की यह पहल एनसीपी प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चीनी उद्योग की स्थिति पर पत्र लिखे जाने के बाद की गई है। पवार ने प्रधानमंत्री से बाजार में चीनी के भारी स्टॉक को देखते हुए तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह किया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, गन्ना उत्पादन अधिक रहने से इस साल अब तक चालू सत्र विपणन सत्र (अक्तूबर - सितंबर) 2017- 18 में चीनी उत्पादन 3.16 करोड़ टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

सूत्र ने बताया, 'प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवों की समिति दोनों के स्तर पर पवार के सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद खाद्य मंत्रालय ने दो-तीन हस्तक्षेपों के साथ मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार किया।' खाद्य मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही चीनी का मिनिमम एक्स-मिल प्राइस 30 रुपये किलो के आसपास तय करने, प्रत्येक मिल के लिए कोटा निर्धारित कर मिलों की स्टॉक सीमा रखे जाने और मिलों के लिए खुले बाजार में चीनी बेचने का मासिक चीनी कोटा जारी करने की व्यवस्था फिर शुरू करने जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव किया है।

चीनी का मिल पर मूल्य इन दिनों 25.60 से 26.22 रुपये प्रति किलो ग्राम के दायरे में चल रहा है। यह दाम उनकी लागत से कम बताया जा रहा है। मिलों का राजस्व बढ़ाने के लिए पवार ने अपने पत्र में कुछ अन्य सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने राज्यों में शीरे के आवागमन, एथेनॉल की बिक्री पर अनाप-शनाप कर लगाने पर रोक का सुझाव दिया है। इसके अलावा उन्होंने एथेनॉल की बिक्री पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने को भी कहा है। सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय एथेनॉल मुद्दे पर जबकि वित्त मंत्रालय चीनी मिलों को वित्तीय पैकेज देने पर गौर कर रहा है। सरकार ने इससे पहले चीनी मिलों को मदद पहुंचाने के लिये गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने में मदद के लिए मिलों को 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पादन सब्सिडी देने को मंजूरी दी थी।

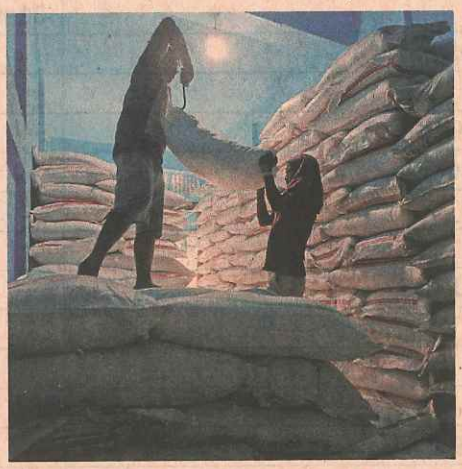

30 लाख टन बफर स्टॉक

- **खाद्य मंत्रालय** ने 30 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने और मिनिमम एक्स-मिल प्राइस 30 रुपये के आसपास तय करने का प्रस्ताव दिया
- **गन्ना उत्पादन** अधिक रहने से इस साल अब तक चालू सत्र विपणन सत्र (अक्तूबर - सितंबर) 2017- 18 में चीनी उत्पादन 3.16 करोड़ टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया

ET
24/5/2018